(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार भविष्य में इस विषय में नई नीति अपनाने का विचार रखती है ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) से (घ) उच्चतर तकनीकी और शैक्षिक संस्थाओं में शिक्षा शुल्कों को और अधिक स्तर पर लाने का प्रस्ताव है ताकि वसूल किए गये शुल्कों और प्रशिक्षण की वास्तविक लागत के बीच कुछ उचित संबंध हो तथापि कठिनाई यह है कि एक औसत भारतीय की अदायगी क्षमता सीमित है और यदि शिक्षा शुल्क में वृद्धि की जाती है तो तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश पाने वाले छात्रों के लिए कुछ ऋण संबंधी प्रबंध करने होंगे जिन्हें वे रोजगार में लग जाने के बाद कुछ समयावधि में वापस लौटा सकते हैं । यह सभी मेधावी छात्रों को अवसर प्रदान करेगा और न कि मात्र उनको जो अधिक शिक्षा शुल्क प्रदान कर सकते हैं ।

मोटे तौर पर यह अनुमान लगाया गया है कि एक आई० आई० टी० स्नातक के प्रशिक्षण की लागत 1 लाख रुपये है जबकि वसूल किया जाने वाला शिक्षा शुल्क नाम मात्र है भारती प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशकों से वास्तविक लागत निकालने के लिए अनुरोध किया गया है।

दिल्ली में नये महाविद्यालयों की स्थापना

74. सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :
श्री राम जेठमलानी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में इस वर्ष स्नातक कक्षाओं में केवल 28076 सीटें उपलब्ध हैं जबकि पात्र विद्यार्थियों की संख्या 57613 है ;

(ख) यदि हां, तो नये महाविद्यालय न खोलने के क्या कारण हैं तथा दिल्ली में कब से कोई नया महाविद्यालय नहीं खोला गया है ;

(ग) क्या छात्रों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए सरकार इस वर्ष नये महाविद्यालय खोलेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्य कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) से (घ) दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुसार, जिन छात्रों ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा (कक्षा-XII) या इसके समकक्ष परीक्षा 40% या इससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण की है, वे छात्र 17 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा पूरी करने पर कालेज में अवरस्नातक पाठ्यक्रम में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश पाने के पात्र हैं ।

दिल्ली विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि 57613 छात्र, जिन्होंने दिल्ली से सीनियर माध्यमिक तथा समकक्ष परीक्षा 40% या इससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण की है, वे विभिन्न अवरस्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के पात्र हैं । इसके मुकाबले विश्वविद्यालयों अवरस्नातक पाठ्यक्रम में 55,386 छात्रों को प्रवेश दे सकता है। इसमें से 29,076 स्थान कालेजों में उपलब्ध हैं, 3510 स्थान नानकालेजियेट हिला शिक्षा बोर्ड में तथा 22,800 स्थान पत्राचार तथा सतत शिक्षा पाठ्यक्रम में हैं । इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 1990-91 से दिल्ली के कई कालेजों में करीब 875 छात्रों की क्षमता वाले विभिन्न नए पाठ्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है । दिल्ली विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि प्रवेश की बढ़ती मांग को देखते हुए दो नए कालेज, एक 300 स्थान वाला पश्चिम दिल्ली कर्मपुरा में तथा

दूसरा 180 स्थान वाला पूर्वी दिल्ली शाहदरा में दिल्ली प्रशासन द्वारा चालू शैक्षिक सत्र से आरंभ किए जा रहे हैं ।

चूंकि कई छात्र प्रवेश के लिए एक साथ एक से अधिक पाठ्यक्रम तथा कई कालेजों में आवेदन करते हैं तथा प्रवेश प्रक्रिया अभी जल रही है अत: प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या तथा कितने छात्रों को प्रवेश नहीं मिल सका, यह अभी ठीक प्रकार से नहीं बताया जा सकता । तथापि, विश्व-विद्यालय ने सुचित किया है कि वह वास्तव में सभी योग्य छात्रों को प्रवेश देने की स्थिति में होगा ।

नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिये विचार-विमर्श

75. श्री अजीत जोगी: क्या **प्रधान मंत्री** 22 मई, 1990 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1427 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई शिक्षा नीति बनाते समय समाज के सभी वर्गों के विशषज्ञों से विचार-विमर्श किया जाएगा ; और

(ख) क्या आदिवासी तथा पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा के विस्तार के संबंध में नई शिक्षा नीति बनाए जाते समय आदि-वासी तथा पिछड़े वर्गों के जन-प्रतिनिधियों से भी विचार-विमर्श किया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और इसके कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए गठित समिति, प्रासंगिक समूहों अथवा व्यक्तियों के साथ यथोचित अन्योन्य क्रिया से समीक्षा करेगी ।

Shift System in Kendriya Vidyalayas

76. SHRI RAM AWADHESH SINGH:

SHRI ANAND PRAKASH GAUTAM.

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some Kendriya Vidyalayas in Delhi are to have two-three shifts;

(b) what are the details of these schools and the circumstances that prompted the Sangathan to introduce the system after its determined opposition thereto;

(c) whether in other cities also the shift system has been introduced or is proposed to be introduced; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI CHIMANBHAI MEHTA) (a) to (d) A proposal to start shift system in Kendriya Vidyalayas in Delhi on experimental basis is under active consideration. Details of Vidyalayas where shift system will be introduced are being worked out. The circumstances which prompted the Sangathan to consider such a proposal has been the heavy backlog of children of transferable Central Government employees seeking admission in Kendriya Vidyalayas. While the pros and cons of the proposal were duly aired, it would not be true to say that there was any "determined opposition" to it.

The shift system is likely to be extended to other major metropolitan towns in due course, depending on the requirement.